



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 21, 2012/चैत्र 1, 1934

No. 74]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 2012/CHAITRA 1, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2012

(मध्यावधि समीक्षा)

विषय : चीन जन.गण. मूल के अथवा वहां से निर्यातित शुष्क सेल बैटरियों पर लागू पाटनरोधी शुल्क से संबंधित मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरुआत।

सं. 15/12/2011-डीजीएडी,—यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात् “पाटनरोधी नियम” कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् “प्राधिकारी” कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा जाएगा) मूल के अथवा वहां से निर्यातित “शुष्क सेल बैटरियों” के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी।

(2) प्राधिकारी द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं. 53/1/2000-डीजीएडी के तहत प्रारंभिक निष्कर्ष जारी किए गए थे और राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 6 फरवरी, 2011 की अधिसूचना सं. 14/2001-सीमा-शुल्क के तहत अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी की अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना 13 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. 53/1/2010-डीजीएडी के तहत प्रकाशित की गई थी। अंतिम निष्कर्ष के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा 2 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. 84/2001-सीमा-शुल्क के तहत 951 GI/2012

संबंधित देश से आयातित संबंधित उत्पाद पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

(3) और यतः, प्राधिकारी ने 31 जनवरी, 2007 की अधिसूचना सं. 53/1/2000-डीजीएडी के तहत यह निष्कर्ष निकाला कि चीन जन. गण. से शुष्क सेल बैटरियों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने से पाटन की अवस्थिति बनी रहेगी या पुनरावृत्ति होगी और इससे क्षति होगी और संबंधित वस्तु के आयात पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की थी। तदनुसार सीमा-शुल्क की दिनांक 13 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना सं. 57/2007 के तहत संबंधित वस्तु पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

(4) यतः, “शुष्क सेल बैटरियों” के घरेलू उत्पादकों की ओर से भारतीय शुष्क सेल विनिर्माता एसोसिएशन ने प्राधिकारी के समक्ष चीन मूल या चीन से निर्यातित शुष्क सेल बैटरियों के पाटन की अवस्थिति बने रहने या पुनरावृत्ति की संभावना का आरोप लगाते हुए अधिनियम एवं नियमों के अनुसार विधिवत् प्रमाणित आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया और पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने तथा उसे जारी रखने का अनुरोध किया।

घरेलू उद्योग

(5) यह आवेदन-पत्र संबंधित वस्तु के घरेलू उत्पादकों की ओर से भारतीय शुष्क सेल विनिर्माता एसोसिएशन ने दायर किया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार संबंधित वस्तु का भारत में होने वाले उत्पादन में आवेदकों का प्रमुख हिस्सा है और अतः पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत वे घरेलू उद्योग हैं।

विचाराधीन उत्पाद और समरूप मद

(6) मूल जांच में अंतर्गत उत्पाद शुष्क बैटरियाँ (विशिष्ट प्राथमिक सेल और बैटरियाँ) थी। यह मध्यावधि समीक्षा जांच होने

के कारण इस जाँच में वह सब उत्पाद शामिल होंगे जो मूल जाँच में थे। यह बैटरियाँ कई रूपों और आकारों में मिलती हैं। तथापि, कागज और धातु (हैवी ड्यूटी एवं सुपर हैवी ड्यूटी दोनों) के बाह्यावरण वाली जिंक कार्बन पेंसिल बैटरियाँ, जिन्हें तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से “आर 6”, “एए”, “यूएम 3” के रूप में माना जाता है, इस जाँच के दायरे में शामिल होंगी। क्षारीय बैटरियाँ पुनः चार्ज करने योग्य बैटरियाँ जैसी अन्य बैटरियाँ वर्तमान जाँच के दायरे से बाहर हैं। विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही होगा जो 13 जुलाई, 2001 को अंतिम निष्कर्ष में अधिसूचित किया गया था।

(7) शुष्क सेल बैटरियों का व्यापक प्रयोग होता है और वे प्राथमिकतः फ्लैश लाइट्स, ट्रान्जिस्टर्स, खिलौनों, दीवार घड़ियों और टेबल क्लॉक, टेप रिकॉर्डर्स, वाकमैन, सीडी प्लेयर्स, रिमोट्स कैमराज, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, डाक एवं तार, रक्षा तथा पुलिस विभाग में उनकी वायरलेस प्रणाली के लिए, सिग्नलिंग के लिए रेलवे में और मौसम विभाग अनुप्रयोगों आदि में प्रयोग की जाती हैं।

(8) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तुएं नियम 2(घ) के आशय के अंतर्गत संबंधित देश से आयातित वस्तुओं के “समरूप मर्दे” हैं। शुष्क सेल बैटरियाँ, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 85 के अंतर्गत अनुसूची-1 के सीमा-शुल्क उप-शीर्ष 8506.10 के अधीन वर्गीकृत हैं। तथापि, सीमा-शुल्क का वर्गीकरण केवल निर्देश के रूप में है और यह किसी भी ढंग से वर्तमान जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं होगा।

प्रारंभिक

(9) प्रामाणिक रूप से विधिवत् दायर आवेदन के मद्देनजर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी संबंधित वस्तुओं पर लगे शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और यह जाँच करने के लिए कि उक्त शुल्क समाप्त करने से पाटन की अवस्थिति बनी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की सम्भावना है या नहीं, एतद्वारा मध्यावधि समीक्षा प्रारम्भ करते हैं।

शामिल देश

(10) इस जाँच में अंतर्ग्रस्त देश चीन जन.गण. है।

जाँच की अवधि

(11) याचिकाकर्ताओं ने अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि को जाँच की अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है। प्राधिकारी ने वर्तमान पुनरीक्षा के उद्देश्य के लिए जाँच की अवधि 1 अप्रैल, 2010 से 30 सितम्बर, 2011 (18 माह) निर्धारित की है। तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं जाँच की अवधि शामिल होगी। पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए जाँच की अवधि के परे के आँकड़ों की भी समीक्षा की जाएगी।

12. प्रक्रिया

(12) यह समीक्षा दिनांक 13 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. 53/1/2000-डीजीएडी (मूल जाँच के अंतिम निष्कर्ष) और दिनांक 31 जनवरी, 2007 की अधिसूचना सं. 53/1/2000-डीजीएडी

(प्रथम मध्यावधि समीक्षा जाँच के अंतिम निष्कर्ष) के सभी पहलुओं को कवर करेगी।

13. इस पुनरीक्षा में अधि विनियमों के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

(14) संबंधित देश के ज्ञात निर्यातक, संबंधित देश की सरकार भारत स्थित उसके राजदूतावास के जरिए, भारत में आयातक और प्रयोगकर्ता, जिनका इस उत्पाद से संबंध है, को निर्धारित प्रपत्र और ढंग से संगत जानकारी प्रस्तुत करने और अपने विचारों से प्राधिकारी को अधोलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है :—

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग, कक्ष सं. 243

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

कोई अन्य पक्षकार भी अधोलिखित समय-सीमा के अंतर्गत इस जाँच से संगत कोई सूचना निर्धारित प्रपत्र में एवं उचित ढंग से भरकर भेज सकता है।

समय-सीमा

(15) मौजूदा समीक्षा से संबंधित कोई सूचना को लिखित में भेजा जाना चाहिए जो इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच जाए। यदि निर्धारित समयवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

(16) सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सुझाव दिया जाता है कि वे इस मामले में अपना हित (हित की प्रकृति सहित) प्रस्तुत करें और अपनी प्रश्नावलियों के उत्तर दर्ज करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन के संबंध में इस जाँच की शुरुआत होने की तारीख से चालिस दिनों के अंदर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें कि पाटनरोधी उपाय करने की आवश्यकता है अथवा नहीं।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

(17) यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोध के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सेटों— (क) एक सेट (शीर्षक, विषय-सूची, पृष्ठों की संख्या आदि सहित) गोपनीय चिन्हित हो और (ख) दूसरा सेट (शीर्षक, विषय-सूची, पृष्ठों की संख्या आदि सहित) अगोपनीय चिन्हित हो, में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में स्पष्ट रूप से “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” लिखा होना चाहिए।

(18) ऐसे किसी चिह्न के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी। गोपनीय तथा अगोपनीय रूपांतर की दो-दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(19) गोपनीय मानी गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रस्तुत की गई सूचना के साथ-साथ इस आशय का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि क्यों ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं किया जा सकता और/अथवा क्यों ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

(20) अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होना चाहिए जिसमें उस सूचना जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है के आधार पर गोपनीय सूचना को सूचीबद्ध किया गया हो अथवा उसका स्थान रिक्त रखा गया हो/सारांश दिया गया हो। अगोपनीय सारांश में पर्याप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का समुचित अर्थ समझा जा सके। तथापि अपवादात्मक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह उल्लेख कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में सारांश न बनाए जा सकने के संतोषजनक कारणों का विवरण निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(21) प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत या सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

(22) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसी कोई सूचना जिसके साथ उसका सार्थक अगोपनीय रूपांतर अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में कारणों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न न हो, को रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के संबंध में अपनी संतुष्टि कर लेने और उसकी आवश्यकता स्वीकारने के बाद ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकार के बिना उसे किसी अन्य पक्ष के समक्ष प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

(23) नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर की सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग

(24) ऐसे मामलों में जहाँ हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से इंकार करते हैं अथवा अन्य प्रकार से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं करते हैं अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डालते हैं तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार का यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2012

(Sunset Review)

Subject : Initiation of Sunset review of Anti-dumping duty imposed on imports of 'Dry Cell Batteries' originating in or exported from China PR.

No. 15/12/2011-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of Anti-Dumping duty on imports of 'Dry Cell Batteries' originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country).

(2) The Preliminary Finding was issued by the Authority *vide* Notification No. 53/1/2000-DGAD, dated 24th January, 2001 and the provisional anti-dumping duty was imposed by the Department of Revenue *vide* Notification No. 14/2001-Customs, dated 6th February, 2001. The final findings notification of the Authority was published *vide* Notification No. 53/1/2000-DGAD, dated 13th July, 2001. On the basis of the final findings, definitive anti-dumping duty on the subject goods imported from the subject country was imposed by the Department of Revenue *vide* notifications 84/2001-Customs, dated 2nd August, 2001.

(3) And whereas *vide* Notification No. 53/1/2000-DGAD, dated 31st January, 2007, the Authority concluded that the cessation of anti-dumping duty on Dry Cell Batteries from China PR will lead to continuation or recurrence of dumping and injury, and recommended continued imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods. Accordingly, definitive anti-dumping duty was imposed on the subject goods *vide* Customs Notification No. 57/2007-Customs, dated 13th April, 2007.

(4) Whereas, Association of Indian Dry Cell Manufacturers on behalf of domestic producers of "Dry Cell Batteries", has filed a duly substantiated application in accordance with the Act and the Rules before the Authority alleging likelihood of continuation of recurrence of dumping of 'Dry Cell Batteries' originating in or exported from China PR and have requested for review and continuation of the anti-dumping duties.

Domestic industry

(5) The application has been filed by Association of Indian Dry Cell Manufacturers on behalf of domestic producers of the subject goods. As per information available on record, the Applicants account for a major proportion in Indian production of the subject goods and therefore constitute the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.

Product under consideration and like Article

(6) The product involved in the original investigation was dry batteries (specifically primary cells and batteries). This being a Sunset review, therefore, the investigation covers the product covered in the original investigation. The batteries are available in various types and sizes. However Zinc Carbon pencil batteries technically and commercially known as "R6", "AA", "UM3" both in paper and metal (both heavy duty and super heavy duty) jacketed from are within the scope of investigation. Other types of batteries such as, alkaline batteries, rechargeable batteries, etc. are beyond the scope of the present investigation. The scope of the product under consideration is the same as notified in the final findings dated 13th July, 2001.

(7) Dry Cell Battery has a broad spectrum of uses and is primarily used in Flashlights, Transistors, Toys, Wall and table clocks, Tape Recorders, Walkman, CD players, Remotes, Cameras, Other electronic equipment, Post & Telegraph, Defence and police for their wireless systems, Railways for signaling and Meteorological applications, etc.

(8) The goods manufactured by the domestic industry are 'like articles' to the goods imported from the subject country within the meaning of Rule 2(d). Dry Cell Batteries are classified under custom sub-heading 8506.10 of Schedule I under Chapter 85 of the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Initiation

(9) In view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the AD Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Country involved

(10) The country involved in this investigation is China PR.

Period of Investigation

(11) The petitioner has proposed 1st April, 2010 to 31st March, 2011 as the period of investigation. The

Authority has fixed the Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st April, 2010 to 30th September, 2011 (18 months). However, injury analysis shall cover the years 2007-08, 2008-09, 2009-10 & POI. The data beyond POI may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

Procedure

(12) The review covers all aspects of Notification No. 53/1/2000/DGAD, dated 13th July, 2001 (final findings of the original investigation), and Notification No. 53/1/2000/DGAD, dated 31st January, 2007 (final findings of the first sunset review investigation).

(13) The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

(14) The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address : The Designated Authority Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties.

Ministry of Commerce and Industry

Department of Commerce

Room No. 243

Udyog Bhavan, New Delhi-110011

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time-limit set out below.

Time-limit

(15) Any information relating to the present review should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

(16) All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire's responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the AD measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis

(17) In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submission, the same

must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or non-confidential" at the top of each page.

(18) Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

(19) For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

(20) The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

(21) The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

(22) Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file

(23) In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

(24) In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority

951 GS/12-2